हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 जुलाई, 1975

खण्ड 3, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 30 जुलाई, 1975

पृश्ठ संख्या

कार्य–मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	(3)1
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)2
वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करना तथा अंतिम प्रतिवेदन पे ा करने का समय बढ़ाना।	(3)2

प्रतिवेदनों पर चर्चाः–	
(1) हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार का प्रतिवेदन	(3)4
(2) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटिड का प्रथम वार्शिक प्रतिवेदन।	(3)4
(3) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटिड का छठा वार्शिक प्रतिवेदन।	(3)14
(4) हरियाणा भाण्डागारण निगम का तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवां प्रतिवेदन।	(3)16
(5) हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यकरण पर वार्शिक प्रतिवेदन।	(3)17

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

कार्य मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 30th July, 1975, be transacted as follows:-

30th July, 1975 at 9.30 A.M.

1. Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.

2. Motion for adjournment of the Sabha Sine-die.

3. Presentation of Preliminary Reports and Extension of time for Presentation of Final Report of the Committee of Privileges.

(i) Presentation of Second Preliminary Report of the Committee of Privileges for publishing news-item in "The

Motherland" dated the 12th July, 1974, and extension of time for presentation of Final Report upto the 15th February, 1976;

(ii) Presentation of Second Preliminary Report of the Committee of Privileges for publishing distorted version of the proceedings of the House in the "Punjab Kesari" dated the 1st December, 1974 and extension of time for presentation of the final Report upto the 15th February, 1976.

(iii) Presentation of the preliminary Report of the Committee of Privileges for writing derogatory remarks against the House and its Members in "Vir Partap" dated the 10th January, 1975 and extension of time for presentation of final Report upto the 15th February, 1976.

4. Discussion on the following Reports

(1) Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the period from 2nd February, 1970 to 30th June, 1972.

(2) First Annual Report of the Haryana State Minor Irrigation (Tube-wells) Corporation Limited for the year 1970-71.

(3) 6th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd., containing the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended on the 31st March, 1973.

(4) 3rd and 4th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1969-70 and 1970-71.

(5) 5th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1971-72.

(6) Annual Report of the working of the Haryana Public Service Commission from 1st April, 1973 to 31st March, 1974.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendation contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this House agrees with the recommendation contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is:-

That this House agrees with the recommendation contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करना तथा अंतिम प्रतिवेदन पे ा करने का समय बढाना

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the Daily Newspaper "The Motherland" for publishing news-item in its issue dated the 12th July, 1974 under the caption "Bansi Lal's throne recoked by three indicents.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: The motion was carried that the time is extended.

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege against Chaudhri Chand Ram, MLA for making a statement and Shri Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher of the Daily Newspaper "Punjab Kesari" for publishing it as also the distorted version of the proceeding of the House in its issue dated 1st December, 1974 under the caption 'विपक्ष हरियाणा विधान सभा के भोश अधिवे ान का बाईकाट करेगा।'

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: The motion was carried that the time is extended.

Shri Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege against Chaudhri Lalit Mohan, Editor and Shri Virender, MA Publisher and Printer of the Daily Newspaper "Vir Partap" Jullundur for writing derogatory remarks against the House and its Members in its issue dated the 10th January, 1975 under the caption 'चौधरी हरदवारी लाल का कसूर क्या है?'

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report of the House be extended upto the 15th February, 1976.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: The motion was carried that the time is extended.

प्रतिवेदनों पर चर्चा

हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार का प्रतिवेदन

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा एवं पंजाब कृशि वि ववविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार के 2 फरवरी, 1970 से 30 जून 1972 तक की अवधि के प्रतिवेदन पर, जोकि 25 जून 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Report of the Haryana Agricultural University, Hisar for the period from 2nd February, 1970 to 30th June, 1972 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricutural Univerisites Act, 1970 which was laid on the Table of the House on the 25th June, 1973 be discussed.

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खडा नहीं हुआ)

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) लिमिटिड का प्रथम वार्शिक प्रतिवेदन

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटिड के वर्श 1970–71 के प्रथम वार्शिक प्रतिवेदन पर जोकि 26 नवम्बर 1974 को सदन की मेज पर रखा गया था चर्चा की जाए–

Mr. Speaker: Motion moved-

That the first Annual Report of the Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Limited for the year 1970-71 which was laid on the Table of the House on the 26th November, 1974 be passed.

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ): स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये यह कहूंगा कि मेरे इलाके के लिए यह एक इम्पोर्टेंट मामला है इसलिये मैं इस पर बोले बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि हरियाणा सरकार ने तहैया कर रखा है इन्होंने कहा है कि हम सब जगह पानी पहुंचायेंगे। जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है और वे इस चीज को कर भी रहे है और इलाके तो ऐसे है जहां पर बडी बडी नहरें और प्राजैक्टस बन रहे है लेकिन हमारा इलाका ऐसा है और भी दूसरे कई ऐसे इलाके है जहां पर माइनर इरिगे ान कारपोरे ान हमारी मदद कर सकती है और लोगों के खेतों को सिंचाई के लिये पानी दे सकती है। जब से इस कारपोरे ान ने काम भाुरू किया है मैं कह सकता हूं ि क इस ने

बहुत अच्छा काम भुरू किया है और उसके टयूबवैल से काफी जमीनों को पानी पहुंचा है। हमारी नारायणगढ की जो तहसील है उसकी जमीन कटी फटी है और वहां यह कारपोरे ा नही लोगों को पानी दे सकती है। दूसरी स्कीम भी बन रही है जिससे सीधे खालों में पानी पहुंच सके और सीधा नालियों में पहुंच कर लोगों के खेतों के लिये पानी मिल सके। इस बारे में मैं एक बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि फंडज की कमी की वजह से ही ऐसा होगा कि जितनी रफतार पहले इस कारपोरे ान के काम की थी उतनी अब नहीं है तो मैं मंत्री जी से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और गवर्नमैंट से निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर पर हमारे इलाका में सिंचाई के लिये यही कारपोरे ान एक सहारा है और वहां पर सिंचाई के लिये दूसरा कोई साधन नहीं है इसलिये हमारे इलाका में इस के लिये फंडज में कटौती न की जायें बल्कि और ज्यादा फंडज दिये जायें। ताकि वहां काम की रफतार में सुस्ती न पडें और जमीनों के लिये पानी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो टयूबवैलज लग जाते है और पुराने हो जाते है उन की पीरियाडीकल चैंकिग की जानी चाहिये। इसकी वजह यह है कि देखा गया है कि कुछ समय के बाद कई टयूबवैलज पानी का डिस्चार्ज कम कर देते हैं। तो बजाय इस के कि लोग इस बारे में ि ाकायत करें, महकमा को चाहिये कि वह अपने आप इस बात की चैंकिग करे कि क्या वजह है कि पानी का डिस्चार्ज कम हो रहा है। यह चैंकिग हर टयूबवैल

की हर 6 महीने या ज्यादा एक साल में जरूर होनी चाहिये ताकि पता लगता रहे कि टयूबवैल कैसे चल रहा है और अगर उस में कोई नुकस हो या नुकस पडने वाला हो तो उसे ठीक किया जा सके ताकि लोगों को नुकसान न हो क्योंकि खराबी आने से लोगों को पानी कम मिलने की वजह से बहुत नुकसान होता है मिसाल के तौर पर अगर 6 इंच पानी आ रहा है तो उससे उतने ही समय में और उतने ही खर्च में ज्यादा जमीन को पानी मिलेगा लेकिन अगर वह डिस्चार्ज को इंच रह जाता है तो खर्च तो उतना ही रहेगा लेकिन पानी कम मिलेगा और थोडी जमीन में आबपा ाी हो सकेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन टयूबवैल की बाकायदा महकमा को अपने आप हर 6 महीने या एक साल के अन्दर चैंकिग करनी चाहिये ताकि लोगों को नुकसान न हो। हमारे जो मंत्री महोदय है उनके पास कृशि भी है एमआईटीसी और बिजली का महकमा भी है। कई दफा देखने में आया है कि एमआईटीसी के जो टयूबवैलज है उनके तैयार हो जाने के बाद और टैस्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद भी छह छह महीने और साल साल भर तक बिजली के कनैक ानज नहीं मिलते है और वे बेकार पडे रहते हैं। इसलिये इस बात की तरफ ध्यान दिया जाये और उनको जल्दी बिजली दिलाई जाये ताकि लोगों को दिक्कत न आये और ऐसा नहीं होने देना चाहिये कि कुआं तो लग गया है लेकिन बिजली न मिलने की वजह से पानी नहीं मिलता है। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं और वह यह है कि जहां जिन गांवों में पीने के पानी की तंगी है वहां पर एमआईटीसी के टयूबवैलज से लोगों को पीने

का पानी दिया जाये। इस बारे में पता लगा है कि पब्लिक हैल्थ वाले एतराज करते हैं कि उनका पानी उनके स्टैंर्ड के मुताबिक नहीं होता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर लोग कुओं से पानी पीते हैं वह भी तो उनके स्टैंर्ड का नहीं होता। लेकिन लोग पीते हैं इसलिये इन कुओं के पानी पर एतराज नहीं होना चाहिये और जब तक पब्लिक हैल्थ वाले पानी का इंतजाम नहीं कर पाते कम से कम उस वक्त तक तो इन कुओं से लोगो को पीने के लिये पानी देने की इजाजत दे देनी चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, इस वक्त सदन में माइनर इरिगे ान (टयूबवैल) कारपोरे ान की वर्श 1970–71 की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इसमें कोई भाक नहीं है कि इस कारपोरे ान ने बेहतरीन काम किया है और लोगों को खेतों के लिये पानी दिया है जहां पर कि नहरों का पानी नहीं पहुंचता है। इस रिपोर्ट में जिकर किया गया है।

“Running and Maintenance of Tubewells”:

At the time of the formation of company 637 Direct Irrigation Tubewells were taken over out of which 616 were in operation. During the year 47 additional Director Irrigation Tubewells were drilled, but 36 were brought into operation. Thus a total of 652 Direct Irrigation Tubewells were put into operation by March, 1971.

इस कारपोरे ान ने 200 टयूबवैल नारायणगढ में और 31 डायरैक्ट टयूबवैल इरीगे ान के लिये कृश्णावती बैल्ट में लगाये है और वे successfully काम कर रहे हैं लेकिन स्पीकर साहब, इस बारे में मैं दो तीन बातें सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । मेरी बवानी खेडा तहसील में नहरों से इरीगे ान की फैसिलिटीज पूरी नहीं है क्योंकि सारी तहसील टेल पर वाक्या है जिस की वजह से इरीगे ान फैसिलिटीज पूरी नहीं मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर इस कारपोरे ान की तरफ से डीप बोरिंग टयूबवैलज टैस्ट कराये जायें और हजार फुट की गहराई तक आबपा ी के लिये डीप बोरिंग टयूबवैलज टैस्ट कराये जायें। पहले हमारे जिला भिवानी में कोई भी इरिगे ान के साधन नहीं थे लेकिन जब 6/7 साल की कोि ा ाों के बाद वहां के किसानों को इतनी राहत मिली है कि वे अपने खाने के गुजारा लायक कनक और दूसरा अनाज पैदा करने के काबिल हो गये हैं लेकिन आबपा ी की इतनी फेसिलिटीज आज भी वहां पर नहीं है जितनी फेसिलिटीज करनाल और कुरूक्षेत्र से पचास साल पीछे है। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार को वहां पूरे साधन जुटाने चाहिए और वहां कि किसानों को पानी की पुरी फेसिलिटीज महैया की जानी चाहिये। इसके लिये मैं दो सुझाव देता हूं एक तो यह कि वहां पर डीप बोरिंग टयूबवैल टैस्ट कराये जायें ताकि पानी की सप्लाई बढ सके। दूसरे यह कि जितने भी माइनर, नाले, नालियां और खाल वगैरह है उनको पक्का किया जाये। बहुत सारे हल्को में मैंने सुना है कि वहां के एमएलए

साहिबान कहते है कि उनके यहां की नालियां पक्की न कराई जायें लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिला भिवानी के सारे माइनर नाले नालियां और डिस्ट्रीब्यूट्रीज पक्के होने चाहिए ताकि लोगों के लिये इरिगे ान फेसिलिटीज बढ सके। हमारे यहां जैसे सुन्दर ब्रांच है और उससे स्पीकर साहब, आपके इलाके को भी पानी लगता है वह 34/35 मील की डिस्ट्रीब्यूट्री है उसे पक्का करने से 10/15 फीसदी पानी बढ सकता है। इसी तरह से बवानी खेडा माइनर है खानक माइनर बगैरह जो दूसरे माइनर है अगर इन सारे माइनर्ज को पक्का कर दिया जाये इस कारपोरे ान को जो काम देकर या दूसरे साधनों से उनकी अगर लाइनिंग कर दी जाये तो किसान को 10/15 फीसदी एडी ानल पानी मिल सकेगा। इसके अलावा जहां तक इस कारपोरे ान का ताल्लुक है अब तक हिसार जिला में कुछ इलाकों में वाटर कोर्सिज की लाइनिंग की गई है। उन लोगों का इस बारे में reaction यह है कि टेल पर खेत वहां होते थे और पानी लगाते वक्त दो आदमी पीछे लगाने पडते थे एक पीछे सम्भालने के लिये दूसरा खेत में पानी लगाने के लिये लेकिन अब कारपोरे ान ने यह जो काम किया है इससे लोगों की लेबर बची है और उनको राहत मिली है तो मैं अर्ज करता हूं कि जिला भिवानी और महेंद्रगढ के फैमिन स्ट्रिकम एरियाज की तरफ जैसे मैं ने मुझाव दिया ध्यान दें। इस साल तो कुदरत ने कृपा की है और सात आठ साल के बाद बारि ा हो गई है और लोग कहते हैं कि अगर यह एमरजैंसी न लगती और यह सख्ती न होती तो यह बारि ा भी न होती। तो

यह जो सख्त कदम उठाये गये हैं इनसे कुदरत भी खु ा हुई है और जहां पहले कई साल से बारि ा नहीं हई थी वहां बारि ा हो गई है। तो मैं अब ज्यादा न कहता हुआ अपना स्थान लेता हूं और निवेदन करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाये।

मलिक सतराम दास बतरा (कलानौर): स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस माईनर इरिगे ान कारपोरे ान ने जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है और बहुत से जिलों में इस ने टयूबवैलज लगाए है। यह जो नालियों को पक्का करने का काम है यह जगह जगह हो रहा है लेकिन एक बात की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन को पक्का करने के लिए पत्थर लगा रहे हैं जहां खुदी नालियां है वहां तो पत्थर टिक जाता है लेकिन जहां पर फिलिंग होनी है वहां पर पत्थर नहीं टिक पाता है और नतीजा ठीक नहीं निकलता है नुकसान होता है। वहां पर अगर पत्थर की बजाय ईंटे लगाई जाये ंतो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार ने ईंटें बनाने के लिए कोयला दिया है और ईंटें 72 रूपये के भाव से देती है। अगर नालियां ईंटों से बनाई जाएं तो किसान खु ा होता है और इस काम के लिए अगर उसको 105 रूपये के भाव से ईंटें लेनी पडे तो ले सकता है। जमींदार आजकल स्लेट की नालियां बनाता है। मैं आपसे गुजारि ा करूंगा कि पत्थर की जगह ईंटे इस्तेमाल की जाएं। ईंट की नालियां ज्यादा पक्की बनती है। जो सुपरवाइजर इस काम को

करवाते हैं वे इस पर गौर करें। इस में जो लेबर लगती है मुलाजम अपना टाईम लगाते हैं बिल बनाते हैं इन सभी चीजों का सारा खर्च जमींदारों के नाम होता है लेकिन पत्थर से नालियां ठीक नहीं बनती। इसलिए जमीदारों की एक सुपरवीजन कमेटी बना दी जाए ताकि वह कमेटी इस काम को सुपरवाईज करती रहे और कहीं पर कोई गडबड घोटाला न हो। यह बात मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता था। यह ठीक है कि पत्थर का रेट ईंट की निस्बत ज्यादा है 6 रूपये ईंट पडती है और 8 रूपये पत्थर पडता है इसलिए आपके द्वारा सरकार से आग्रह करूंगा कि नालियां की फिलिंग जहां पत्थर से होती है वहां ईंट से हो तो ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, मैं दो चार मिनट इस विशय पर बोलंगा। वैसे तो मैंने रिपोर्ट पढी है एमआईटीसी का काम बडा तसल्लीबख्भा है लेकिन एक बात हाउस की नालेज में लाना चाहता हूं जैसा कि मैंने अनुभव किया है कई दफा कुछ कामों में कंट्रैक्टर्ज या अफसरान की वजह से पब्लिक फण्ड काफी जाया हो जाता है। मिसाल के तौर पर टयूबवैल की खुदाई होती है कई बार पानी निकलता ही नहीं, सारी महेनत और पैसा जाया जाता है अगर पानी निकला भी तो लीकेज हो जाता है इस सारे काम में 6 महीने से एक साल तक का समय लग जाता है जिससे फण्ड जाया होता है इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां एमरजैंसी पब्लिक पर है वहां कंट्रैक्टर्ज और आफिसर्ज पर

भी होनी चाहिए उनको भी पब्लिक फण्ड का ख्याल रखना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। फरीदाबाद ब्लाक में गांव निवादा की काफी जमीन में पानी भर गया है पता नहीं एमआईटीसी का टयूबवैल लीक हुआ है या थर्मल प्लांट का टैंक लीक हुआ है। सारे देहात में पानी ही पानी भर गया। मैंने एसडीएम और डीसी से इस बात का जिकर किया लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस लीकेज से नुकसान यह हुआ है जितने एरियें में पानी फैला हुआ है उस में मलेरिया फैल गया है। वैसे तो सरकार की कोि ा ा से फरीदाबाद के भाहरी और देहाती इलाके में एक मच्छर भी नहीं छोडा है। सब खत्म हो गए। इस कृपा के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और हरियाणा सरकार का म ाकूर हूं। इस में हाउस तालियां बजाएगा और खु ा होगा लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस पानी की लीकेज बन्द की जाए क्योंकि आस पास के इलाके में मच्छर फैल गया है। पता नहीं एमआईटीसी का टयूबवैल लीक हुआ है या थर्मल प्लांट की टंकी लीक हुई है। इस लीकेज की रिस्पोसिंबिलिटी उस कंट्रैक्टर पर फिक्स की जाए और उसे पूछा जाएं कि क्यों पानी लीक हुआ। इस ि ाकायत को नोटिस में लायें हुए दो महीने हुए है लेकिन अभी तक उसका हल क्यों हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

श्री रामधारी गौडः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा के चप्पे चप्पे में पानी पहुंचाने का ताल्लुक है उसमें

एमआईटीसी बहुत बडा रोल अदा कर रही है। कुछ ऐसे इलाके है जहां नहरों का पानी नहीं पहुंच सकता जैसे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का इलाका है या और भी कई ऐसे इलाके है जहां पानी की दिक्कत है। आज कल पानी बचाने के लिए पक्के खाल बनाने का आन्दोलन चला है एक कार्यकम चला है इस संबंध में मैं एक सुझाव दूंगा। सुझाव यह है कि जब खाल बनाए जांए वे काफी उंचा ले जाकर बनाए जाएं ताकि जहां उंची जमीन है जिस में पानी नहीं पहुंचता उंचे खाल होने से पानी पहुंच जाए। इन खालों को बनाने में मैटीरियल भी अच्छा लगना चाहिए। कई जगह ऐसा हो जाता है कि मैटिरीयल सब स्टैंर्ड का लगा देते हैं और बाद में खाल टूट जाते है। इस काम की चैंकिग होनी चाहिए क्योंकि खाल मुदती चीज है इनसे काफी सालों तक काम लेना होता है अगर किसी कारण बीच में होल हो जाए सब–स्टैंर्ड मैटिरीयल होने के कारण टूट जाए तो बडा नुकसान होता है क्योंकि पक्के खाल का टूटना कच्चे खाल की निस्बत ज्यादा नुकसानदेह है। कच्चे खाल को मिटटी डालकर बन्द किया जा सकता है लेकिन अगर किसी पक्के खाल से थोडा बहुत पानी लीक होने लग जाए तो वह बन्द नहीं होता। इस बात की तरफ खास ध्यान देने की आव यकता है।

दूसरी बात यह है कि कुछ इलाके ऐसे है जहां सब–सायल वाटर बहुत सेलाईन है बहुत कडवा है पीने के लायक नहीं है। जमींदार के पास इतने साधन नहीं होते कि वह नीचे

गहराई तक पहुंच सके और बोरिंग करके मीठा पानी नीचे से ला सके। यह उसके बस की बात नहीं है ऐसी जगहों पर एमआईटीसी को टैस्ट बोरिंग के तौर पर काम करना चाहिए क्योकि कई जगहों पर पानी खारा होता है और उसके नीचे मीठा होता है इस मीठे पानी को निकालने के लिए एमआईटीसी को कार्य करना चाहिए। वैसे एमआईटीसी का कार्यक्रम बहुत अच्छा है लोगों को इससे बहुत सहायता मिलेगी प्रोडक ान भी बढेगी। मैं इस मकहमे के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

चौधरी मेहर सिंह (बडोपल): स्पीकर साहब, इस दि ाा में जो काम हुए है उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मसलन औगमेंटे ान टयूबवैल को बनाने में कमाल कर दिया, डायरैक्ट टयूबवैल का काम भी काबले तारीफ है। लेकिन एक बात यहां कहने के काबिल है कि जहां पर लाइनिंग आफ वाटर कोर्सिज है वहां ि ाकायत ही ि ाकायत है। इसके मुताल्लिक मेरा एक सुझाव है और आपकी मारफत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि लाइनिंग आफ वाटर कोर्सिज पर जो खर्चा आता है वह जमींदार के सिर पर है। इसके चार्जिज भी बडे हाई है अब तो भाुक्र है परमात्मा का कि बारि ा हो गई और कुछ मीसा ने पकड धकड कर ली जिससे टिकटिकाव हो गया क्योंकि लोगों को भडकाया जा रहा था कि गवर्नमेंट पैसा खा गई। गवर्नमेंट ने पैसा तो क्या खाना था लेकिन एक बात जरूर है कि चार्जिज बडे हाई थे, एक्सपैंडीचर बहुत ज्यादा है इसकी सकूटनी ही जाए।

एमआईटीसी वाले सोचते है कि इस खर्चे की रिकवरी कल्टीवेटर से होनी है इसलिए जितना चाहेा उतना खर्च कर दो। अगर सरकार एक्सपैंडीचर कम करने के लिए एक कमेटी बना दे जिस में concerned cultivators को associate कर दिया जाए तो खर्च में कमी हो सकती है। वह कमेटी देखेगी कि वाटर कोर्सिज का लैवल ठीक है या नहीं, मैटीरियल ठीक यूज हो रहा है या नहीं रहा टूट–फूट तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गलत लाइनिंग करके बना दिया और 10 दिन के बाद टूट जाएं। अगर कल्टीवेटर्ज की एक कमेटी बना दी जाए तो मेरे ख्याल में ि ाकायतें दूर हो जायेगी और लोगों की सैटिसफैक ान भी हो जाएगी। अब तो वे कहते हैं कि इस काम पर रूपया भी बहुत लगता है और काम भी ठीक से नहीं हो पाता, गवर्नमेंट पूछती ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह मेरा सुझाव है अगर इस पर सरकार द्वारा गौर कर लिया जाए तो बडी कृपा होगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुकिया अदा करता हूं।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, माइनर **10.00 बजे** इरिगे ान (टयूबवैल) कारपोरे ान की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है मैं तो चाहता था कि मैम्बर साहिबान कारपोरे ान की इस रिपोर्ट पर और कारपोरे ान द्वारा किए गए कामों पर बडी विस्तारपूर्वक चर्चा करते परन्तु जो कुछ साथी मैम्बरान बोले हैं और जो सुझाव उन्होंने दिए है उनके संबंध में मैं कुछ बातें आपके सामने निवेदन करूंगा। वैसे तो

अध्यक्ष महोदय हमारा माइनर इरिगे ान कारपोरे ान एक भाानदार आर्गेनाइजे ान है जिसने बडा भारी काम न केवल अपने प्रदे ा में किया है बल्कि दूसरे प्रदे ाों में जाकर भी अपने काम का रिकार्ड कायम किया है। अध्यक्ष महोदय, सन 1970 में यह कारपोरे ान बना। उस समय केवल 279 औगमेंटे ान टयूबवैल और 616 डायरैक्ट टयूबवैल प्रदे ा में थे। उन्हें संभालने के प चात और काम इस दि ाा में कारपोरे ान ने किया और तमाम हरियाणा में डायरैक्ट इरिगे ान टयूबवैलज की संख्या 1039 है तथा औगमेंटे ान टयूबवैलज की संख्या लगभग 2000 है। इन डायरैक्ट इरिगे ान टयूबवैलज के द्वारा तकरीबन 118000 एकड भूमि को पानी दिया जाता है। यह वह जमीन है जिस जमीन को किसी प्रकार की सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस टयूबवैल कारपोरे ान ने अध्यक्ष महोदय बिहार सरकार की प्रार्थना पर वहां जाकर भी कम किया और अढाई करोड रूपये का कांट्रैक्ट बिहार सरकार के साथ किया। आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि हमारे कारपोरे ान ने इतने अच्छे ढंग से काम किया कि बिहार सरकार और बिहार के अधिकारी आज तक हमारे काम की सराहना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां हमने दे ा के एक प्रदे ा में उनकी सिंचाई सुविधाएं बढाने में इतना काम किया वहां हमारे कारपोरे ान ने भी तकरीबन 30 लाख रूपये का मुनाफा उस काम में कमाया। आपको यह जानकार प्रसन्नता होगी कि और प्रदे ा सरकारें भी अब हमसे इस बात की प्रार्थना कर रही है कि यह कारपोरे ान उनके वहां जाकर काम करें। अभी उडीसा सरकार ने

माइनर इरिगे ान कारपोरे ान से रिक्वैस्ट की है कि तीन सौ टयूबवैलज उनके यहां लगाए जाएं। तीन करोउ रूपये का वह काम है। बातचीत चल रही है जैसे ही हमारी यह नैगोसिएई ान सफल होगी, हमारा यह कारपोरे ान वहां जाकर काम करेगा। तो इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, यह कारपोरे ान न केवल हरियाणा प्रदे ा में बल्कि हमारे राश्ट्र के अन्य प्रदे ाों में जाकर भी दे ा की खाद्य समस्या को हल करने में अन्न का उत्पादन बढाने में बडा भारी योगदान कर रहा है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय माइनर इरिगे ान (टयूबवैलज) कारपोरे ान ने खाल पक्के करने का काम अपने हाथ मैं लिया है। एआरसी की तरफ से जो फंड हमें दिया जाता है उस धन का उपयोग खाल पक्का करने में किया जाता है। अब तक एआरसी ने 877 वाटर कोर्सिज को पक्का करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इन सब खालों को पक्का करने में 105500000 रूपये अध्यक्ष महोदय खर्च होंगे। खाल पक्का करने का काम हमारे प्रदे ा में फतेहाबाद, सिरसा, रोडी, हिसार, रोहतक और भिवानी के इलाके में चल रहा है। अब तक जो खाल पक्के किए गए उनकी संख्या 346 है। प्रत्येक खाल की औसत लम्बाई 8500 फुट के लगभग होती है और साढे तीन करोड रूपये अब तक हमने खाल पक्के करने पर तमाम प्रदे ा में खर्च किए है। यह एक बडा भारी काम है और इतना भारी काम है कि खाल पक्के करने से जो सीपेज होती है जो पानी के लौसिज है उनको किसी हद तक

पूर्ण रूप से रोक पाते हैं। खाल अगर पक्के कर दिए जाएं तो 20–25 प्रति ात तक पानी की बचत हो जाती है। तो यह एक बडा भाानदार काम है अब तक जितने खाल पक्के किए हैं उससे 150 क्यूसिकस पानी हमने बचाया है। 150 क्यूसिक्स पानी काफी पानी होता है जिसे हम ऐक्सट्रा एरिया को दे सकते है या सिंचाई अधीन जो क्षेत्र है उसको अधिक मात्रा में पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार खाल पक्का करने का और टयूबवैलज लगाने का काम चलता है।

अध्यक्ष महोदय, टिक्का जगजीत सिंह ने जो हमारे सम्मानित सदस्य है और नारायणगढ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ सुझाव यहां रखे है। दो सौ के लगभग डीप टयूबवैल्ज इनके क्षेत्र में लगे है यह वह इलाका है जो सब–माउंटेनियस है जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, नदी नाले यहां खूब है लेकिन फिर भी सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं था। हमारे इस कारपोरे ान ने डीप टयूबवैल्ज लगाकर के उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक बडा भाानदार काम किया है। टिकका साहब ने एक सुझाव तो यह रखा कि नलकूप वहां और लगाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नलकूप लगाने की स्पीड कुछ धीमी हो गई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है जैसा मैंने पहले कहा कि खाल पक्का करने और डायरैक्ट इरिगे ान टयूबवैलज लगाने के लिए जो पैसा मिलता है वह एआरसी से मिलता है। कुछ दिनों से एआसी से धन प्राप्त करने में कुछ

कठिनाई हो रही है। आप जानते है सारे दे ा की आर्थिक स्थिति पिछले दिनों में कुछ गंभीर रही है और उसका प्रभाव एआरसी पर भी हुआ है लेकिन हम पूरी चेश्टा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड हमें मिले ताकि उससे हम ज्यादा से ज्यादा टयूबवैलज जहां जहां आव यकता है जहां जहां उन्हें लगाने का स्कोप है लगाएं। अध्यक्ष महोदय, इस साल 1975–76 में तीन सौ डायरैक्ट इरिगे ान टयूबवैल्ज लगाने का हमारा प्रोग्राम है। यदि हमें जितनी आव यकता है उतना धन उपलब्ध हो गया तो जरूरी तौर पर इस काम को हम पूरा करेंगे। यह तो आप जानते ही है कि हमारे कारपोरे ान की काम करने की क्षमता काम करने की भाक्ति बडी भारी है। जब यह दूसरे प्रदे ा में प्र ांसनीय काम कर सकता है तो अपने प्रदे ा में कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा काम कर सकता है लेकिन कठिनाई धन की है अगर धन आव यकतानुसार और समय पर मिल गया तो हम इस काम को अव य पूरा करेंगे और जो गति में कुछ धीमापन आया है उसको और ज्यादा तेज करेंगे।

स्पीकर साहब, टिक्का साहब ने और भाायद एक दूसरे सज्जन ने भी यह बात कही कि जो टयूबवैलज चल रहे है उनकी भी पूरी तरह चैकिंग की जाए। यह बात ठीक है मेरे पास भी इस किस्म की ि ाकायतें आती है कि मीटर खराब हो जाने पर, पम्प में नुक्स हो जाने पर या किसी और प्रकार की अडचन आ जाने पर उसकी ठीक जांच नहीं होती और समय पर आ वासन देता हूं

कि हम इसका पूरा प्रबन्ध करेंगे और ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि बहुत ज्यादा समय तक कोई टयूबवैलज बेकार न पडा रहे।

टिक्का साहब ने एक बात यह कही कि टयूबवैल की बोरिंग हो चुकी है म ीन लग चुकी है पम्पिंग सैट लग चुका है लेकिन बिजली नहीं मिलती। बिजली की बात ऐसी है अध्यक्ष महोदय कि यह मुकदमा भी मेरे पास है और यह बहाना नहीं कर सकता कि बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड इस काम को नहीं करता लेकिन अपनी कठिनाई जरूर आपके सामने रखता हूं। वहां भी फंड की कुछ कमी है जिसकी वजह से हम पूरी मात्रा में सामान नहीं खरीद पाते और टयूबवैलज की बहुत सी टैस्ट रिपोर्टस जो हमारे पास पडी है उनको हम ऐनरजाइज नहीं कर पाते। लेकिन इस बात की पूरी कोि ा ा कर रहे हैं कि जहां से भी फंड मिल सकें वह प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी जितनी टैस्ट रिपोर्टस हमारे पास पडी है उन सारे टयूबवैलज को चाहे वे भौलो टयूबवैल्ज है ऐनरजाइज करेंगे। टिक्का साहब ने एक सुझाव यह भी दिया है कि एमआईटीसी जहां इरिगे ान के लिए पानी देता है वहां पीने का पानी भी इन टयूबवैल्ज से दिया करे। यह सुझाव मेरे पास पहले भी आया था। पहले तो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास था और मैंने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से विचार–विम र्ा भी किया था। जो बात टिकका साहब ने कही है और जो दलील उन्होंने मुझे दी है वह मैं मानता हूं। गांव में लोग अपने स्टैंर्ड के मुताबिक कुओं से ही पानी निकालकर पीते हैं। मैं

भी यह चाहता हूं कि जब तक जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीने के पानी का कोई प्रबन्ध न हो एमआईटीसी नलकूपों से पानी देने का प्रबन्ध करे। हम पानी देने के लिए तैयार है यदि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट पानी लेने के लिए तैयार हो।

चौधरी अमर सिंह जी ने जो कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी कठिनाई भी उचित है मैं भी मानता हूं कि बवानी खेडा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि उस सारे एरिया में पानी की दिक्कत है। वह मेरा पडौसी हल्का है वहां पर जो भी काम हो रहा है एक एक काम की स्थिति का मुझे पूरी तरह पता है लेकिन अध्यक्ष महोदय जहां तक उस एरिया में टयूबवैल लगाने का सम्बन्ध है वहां पर ग्राउंड वाटर ठीक नहीं है। मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। जहां तक ट्रायल बोरिंग करवाने का संबंध है उसके लिए ग्रांउड वाटर बोर्ड गवर्नमेंट आफ इंडिया का बना हुआ है। वह ग्रांउड वाटर को टैस्ट करता है। उसमें हमारे अपने अधिकारी भी हैं टैक्नीकल आदमी भी है वाटर को टैस्ट करता है उसमें हमारे अपने अधिकारी भी है टैक्नीकल आदमी भी है उन्होंने तमाम स्टेट का सर्वे किया है कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में अंडर ग्रांउड पानी मीठा है जहां पर टयूबवैल लग सकते है। यदि कहीं किसी भी प्रकार की गुजांइ ा है तो हम ट्रायल बोरिंग करवा कर देख लेगें। अगर मीठा पानी ठीक मिकदार में उपलब्ध हुआ जो कृशि के लिए उपयोगी हो तो वहां के लिए योजना तैयार करायेंगे।

एक बात चौधरी अमर सिंह जी ने यह कही कि नदी नाले और खाल भी पक्के होने चाहिए। जहां तक नहर और माइनरों के पक्के करने का सवाल है यह तो एमआईटीसी का काम नहीं है। एमआईटीसी तो प्राइवेट खालों को पक्का करती है लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि इरिगे ान डिपार्टमेंट मेरे पास है इसलिए उसके विशय में भी अर्ज कर दूं। सुन्दर ब्रांच का हम अस्टीमेट तैयार करवा रहे है कि उसको पक्का किया जाए। हम उसके लिए पूरी पूरी कोि ा ा करेंगे कि सारी ब्रांच एक साथ नही ंतो उसका कुछ हिस्सा जहां पर कट ज्यादा होते है अथवा पानी का नुकसान अधिक होता है उसको पक्का कर दिया जाए। जहां तक खाल पक्के करने का सम्बन्घ है उसके लिए एआरसी से कर्जा मिलता है। उससे हम इन खालों को पक्का कराते हैं।

श्री सतराम दास बत्रा जी ने भी एक एतराज किया है। उन्होंने कहा कि जहां पर हम खाल पक्के करवा रहे हैं उनमें पत्थर न लगवाएं जाएं। इस प्रकार की ि ाकायतें मेरे पास भी आई है। जहां पर खुदाई के खाल है। अगर वहां पर बैंड में और साइडों में पत्थर लगा दिए जांए तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने खुद जाकर देखा है पत्थर के खाल ज्यादा पुख्ता होते है लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बधाई के खाल है और सैंडी एरिया है वहां पर पत्थर काम नहीं करता है क्योंकि सैंडी एरिया में रेत पत्थर को स्पोर्ट से खिसकता है और इस कारण से खाल टूट जाता है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा ईंटें इस्तेमाल करने का

सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि पत्थर बे ाक बैड में इस्तेमाल कर लिया जाए और कम से कम साइड में ईंटें लगा दी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। पिछले दिनों आपको पता है ईंटों की काफी डिफिकल्टी थी ईंटें मिलती नहीं थी। ईंटें पकाने के लिए कोयला उपलब्ध नहीं था इसलिए हम अधिक ईंट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। काम को जो हाथ में लिया हुआ था उसको छोड नहीं सकते थे क्योंकि एआसी ने रूपया सैक ान किया हुआ था। अगर उस अर्से के अन्दर हम काम नहीं करते तो हमारा लोन भी जब्त हो जाता और जो हमने 150 क्यूसिक पानी सीपेज से बचाया है यह भी न बच पाता और जो हमारा काम था वह पूरा नहीं हो पाता। अब हमारी यह कोि ा ा है कि ईंटे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाएं।

श्री रामधारी गौड ने एक बात कही कि एमआईटीसी जो मैटीरियल इस्तेमाल करता है वह सब स्टैंर्ड का होता है ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस विशय में पूरी तरह से जांच रखते है देखरेख होती है। हमारे अफसर भी इस बारे में पूरा ध्यान रखते है और मैं भी मौके पर जाकर देखता रहता हूं। मैं खुद फील्ड में गया हूं और मैटीरियल को मैंने चैक किया है। अभी पिछले दिनों मैं सिरसे के हल्के में गया था। वहां पर मुझे एक स्थान पर सब स्टैंर्ड मैटीरियल लगता हुआ मिला। मैंने उसी वक्त वहां के एक्सईएन ओवरसीयर, एसडीओ को सस्पैंड किया और सख्त वारनिंग दी कि कहीं भी सब–स्टैंर्ड मैटीरियल प्रयोग किया गया

तो हम माफ नहीं करेगें। जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है जिसमें हमारे किसान भी भाामिल हो, उस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे किसान जहां पर खाल बन रहे है अपने तरीके से सुपरवीजन करें। यह बात ठीक है कि इन खालों के पूरा करने के बाद वह पैसा किसानों ने, का तकारों ने देना है। किसानों ने इस पैसे का ब्याज भी देना है इसलिए यदि कहीं खराब काम होता है तो नुकसान किसानों का होता है। किसान अपने अपने खेत में जाकर जहां पर वाटर कोर्स बन रहे है खुद सुपरवीजन करें जैसें उनकी अपनी हवेली, मकान या कमरा बन रहा है क्योकि इसकी कीमत किसान ने देनी है। इसलिए उनको खुद सुपरवीजन करनी चाहिए। जहां पर कमी नजर आए तो मेरे पास डायरैक्ट आएं या हमारे अधिकारियों के पास आएं। हम वहां पर पूरा ऐक ान लेंगे। कोई भी सब स्टैडर्ड मैटीरियल लगाता है किसी भी माइनर पर या किसी भी खाल पर हम नहीं लगने देंगे।

जिन जिन बातों के बारे में मैम्बर साहिबान ने यहां पर जिकर किया उनके बारे में मैंने जवाब दे दिया है। एक बात और नलकूपों की रिपेयर के बारे में है। उसके बारे में भी हम पूरी तरह से चैकिंग करेंगे। जहां कहीं भी टूट फूट होगी वहां पर रिपेयर का प्रबन्ध करेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस रिपोर्ट को देखकर जो काम एमआईटीसी ने किया है उसकी सराहना की जाए।

हरियाणा राज्य के औद्योगिक विकास निगम लिमिटिड का छठा वार्शिक प्रतिवेदन–

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to move-

That the 6th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd., containing the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended on the 31st March, 1973, which was laid on the Table of the House on the 26th November, 1974 be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the 6th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd., containing the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended on the 31st March, 1973, which was laid on the Table of the House on the 26th November, 1974 be discussed.

श्री अमर सिंह (बवानी खेडा एस0सी0): स्पीकर साहब, हमारा दे ा आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हर आदमी को काम मुहैया होना चाहिए। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान एग्रीकल्चर पर डिपैड करने वाला दे ा है। इसी कारण से इसको किसान दे ा कहा जाता है। भारतवर्श में आज एग्रीकल्चर पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता और न ही यह हो सकता है कि सब लोगों को एक ही भाोबे में काम मिले। जिस प्रकार से हम एग्रीकल्चर पर डिपैंड करते हैं उसी प्रकार से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक ान पर भी डिपैंड करते हैं। इंडस्ट्रियल आफ दी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल

डिवैल्पमेंट कारपोरे ान लिमिटिड जेरे बहस है इसमें बहुत सी चीजें मैंने देखी है जो इसमें अलग अलग काम कर रही है जैसे टैनरी, सिग्रेट प्रोजैक्ट है, ग्लास बोटल्ज प्राजैक्ट आदि ये जितने भी प्राजैक्ट हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक ान बढी है उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक ान तभी बढेगी जब सभी लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। जितने भी बिग प्राजैक्ट है उनके साथ साथ स्माल प्राजैक्ट भी देहात में लगाए जाएं। हिन्दुस्तान में देहात में ज्यादा लोग बसते हैं। वहां पर अन–एम्पलायमेंट ज्यादा है। एग्रीकल्चर पर काम करने वाले लोग ज्यादा है जो साल में नौ महीने बेकार रहते हैं और जिसके पास तीन महीने काम रहता है। जो खेती–बाडी का काम करने वाले लोग है उनको भी दस्तकारी के साधन जुटा दिये जाये ंतो अच्छी बात है। जैसे हैरो बनाने और ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिट लगाकर देहात के लोगों को काम दिया जायें और इसके लिये यह कारपोरे ान उनको लोन एडवान्स करें। मेरा कहना यह है कि जो लैंडलैस लेबरर्ज है उनको स्माल स्केल यूनिटस लगाने के लिये यह कारपोरे ान लोन दे और उस तरह से दे जैसे कि नै ानलाइज्ड बैंक्स से पिछले दिनों गरीबों को लोन मिला। वह लोन बहुत सी जगह पर पर्सनल सिक्योरिटी पर नहीं मिला बल्कि उसके लिये और बहुत सी चीजें मांगते रहे जिसकी वजह से थोडे दिनों के बाद यह फिर बन्द हो गया। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट कारपोरे ान की तरफ से लैंडलैस लेबरर्ज को या फारमर्ज को

देहात में अपने छोटे छोटे काम लगाने के लिये और उनको ऐम्पलायमेंट देने के लिये पर्सनल सिक्योरिटी पर लोन दिया जाये। पर्सनल सिक्योरिटी की बिना पर इस तरह से हो कि जैसे किसी ने स्माल स्केल पर निवार बनाने की फैक्टरी लगानी है तो उसके लिये उसने जो प्लाट लिया है वह प्लैजज हो जायें और फिर उसके बाद जो भी म ाीनरी उसमें वह इन्सटाल करे वह म ाीनरी उस लोन के अगेन्सट प्लैज्ज हो जाये। यह सब उस वक्त तक प्लैज्ज रहे जब तक कि उसके सिर पर लोन बकाया रहे। अगर इस तरह से गरीब देहातियों को दस्तकारी लगाने के लिये लोन दिया जाये और इसके लिये कारपोरे ान में कोई स्पै ाल प्रोवीजन ऐड करा दिया जाये तो मैं यह समझता है कि यह अति लाभदायक होगा और इससे देहात के लोगों को काम भी मिलेगा।

जहां तक जींद में जो हम टैनरी Foreign collaboration से लगा रहे हैं उसका ताल्लुक है उसमें बहुत अधिक काम नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह काम ज्यादा तेजी से होना चाहिए ताकि हजारों भाू–मेकर्स को वहां पर काम मिल सके। इसी तरह से स्पिनिंग मिल का काम भी इस कारपोरे ान ने करना है। उस पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी काम मिल सके। स्पीकर साहब, आज अगर दे ा से गरीबी हटानी है तो हमें सबको काम देना होगा। काम के बगैर तो गरीबी हटती नहीं है काम देने के केवल दो ही तरीके है एक तो खेती बाडी और दूसरा दस्तकारी।

इनके अलावा इस दे ा का काम देने का कोई तीसरा तरीका नहीं है जिससे हम लोगों को एम्पलायमेंट या रोजगार दे सकें। मैं आ ाा करता हूं कि हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब लोगों को रोजगार देने के लिये, दस्तकारी का और ज्यादा फैलाव करने के लिये साधन उपलब्ध करेंगे ताकि हर आदमी जो बेरोजगार है उसको काम मिल सके। और वह अपने गांव पर खडा हो सके। यही कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हू।

श्री ए0के0 गुलाही (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल कारपोरे ान काम बिल्कुल दुरूस्त चला रही है। अब जो लोगों में नई रो ानी का आगाज भाुरू हुआ है उसमें हमें अन–एम्पलायमेंट को सौल्व करना है। नो–लाक–आउट, जो स्ट्राईक और नो रिट्रैंचमैंट ऐसी बातें चल रही है। इस कारपोरे ान का काम यह है कि जहां जहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज घरों में या जगह जगह फैली हुई है उनके लिये अरबन एस्टेट का प्रबन्ध करें ताकि उन स्माल स्केल यूनिटस वालों को एक जगह बसा दिया जाये। इससे उनके काम करने वालों को बहुत सी मु ाीबतें जो होती है वे हल हो जायेगी। मैं मिसाल के तौर पर अपने हल्के फरीदाबाद की ही बात बताता हूं जिसकी वजह से मेरे सामने एक मुसीबत आ खडी हुई है। वहां पर एक कारखाना बाग है जिसमें 10–12 स्माल स्केल यूनिटस है।

उसमें पांच छह सौ मजदूर काम करते हैं। सरकार को वहां दो लाख रूपया टैक्स का आता है। अभी अभी हमारे काम्पलैक्स ने 8 दिन के नोटिस दिये हैं कि गिरा दो लेकिन वहां पर न तो कोई आल्टरनेटिव है और न ही कुछ और है। मैं आपकी मार्फत इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से और लेबर मिनिस्टर से यह कहना चाहूंगा कि आजकल के हालात को देखते हुए कोई ऐसी डिसटरबैन्स पैदा न की जाये जिससे लेबर ट्रबल हो या हालात बिगडें। तो मैं इस रिपोर्ट की सराहना करते हुए यही सुझाव आपके द्वारा हाउस में रखना चाहता था। धन्यवादा।

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, अभी चौधरी अमर सिंह जी ने कुछ सुझाव दिये हैं वे बिल्कुल दुरूस्त है हमरा उनसे कोई डिफरैन्स आफ ओपीनियन नहीं है कि विलेजिज में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। इसके अलावा गुलाही साहब ने एक बात कही है वह भी ठीक है। जहां स्माल स्केल यूनिटस लगे हुए है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं अगर उनके काम में दखल न ही हो तो अच्छा है। एग्रीकल्चर में हम उतने आदमी रोजगार पर नहीं लगा सकते जितने लोगों को आजकल रोजगार को जरूरत है। हमारे पास केवल एक इंडस्ट्री ही है जो उनको एम्पलायमेंट दे सकती है। लेकिन यह सारी बात आज की जो रिपोर्ट अन्डर डिस्क ान है उससे ताल्लुक नहीं रखती। आज की जो रिपोर्ट है यह तो इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट कारपोरे ान की रिपोर्ट है जिस पर डिस्क ान होनी थी। हमारी

कारपोरे ान ने जो काम किया है वह बडा सराहनीय किया है जिसकी वजह से स्टेट में इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट में एक्सपैन्ा ान हुई है। मैं यह समझता हूं कि इस कारपोरे ान ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी यह रिपोर्ट ठीक है।

श्री अमर सिंह जी को पता है कि हमने एक हरिजंज के लिये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने के लिये पिछले सै ान में एक कमेटी अनाउन्स की थी। सीएम साहब ने कहा था कि इसके लिये एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। यह कमेटी बनी हुई है। उसकी दो मीटिंगें भी हो चुकी है और आज भी उसकी मीटिंग हो रही है। हम सोच रहे हैं कि श्री अमर सिंह के सुझाव को उसी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। देहात के जो वीकर सैक ान है और बेरोजगार है हम उनको तेजी से काम देना चाहते हैं। मैं इन भाब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि यह रिपोर्ट बिल्कुल दुरूस्त है इसकी सराहना की जायें।

Mr. Speaker: Sir, Item No. 4 relates to the 3rd and 4th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation and item No. 5 relates to the 5th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation. These may be moved and discussed together.

हरियाणा भाण्डागारण निगम का तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवां प्रतिवेदन।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं–

(1) कि हरियाणा भाण्डागारण निगम के वर्श 1967–70 तथा 1970–71 के तृतीय तथा चतुर्थ वार्शिक प्रतिवेदन पर, जोकि 26 नवम्बर 1974 को सदन की मेज पर रखा गया था चर्चा की जाए।

(2) कि हरियाणा भाण्डागारण निगम के वर्श 1971–72 के पांचवें वार्शिक प्रतिवेदन पर, जोकि 26 नवम्बर 1974 को सदन की मेज पर रखा गया था चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

(1) That the 3rd and 4th Annual Report of the Haryana Warehousing Corpotation for the year 1969-70, which was laid on the Table of the House on the 26th November, 1974, be discussed.

(2) That the 3rd and 4th Annual Report of the Haryana Warehousing Corpotation for the year 1971-72, which was laid on the Table of the House on the 26th November, 1974, be discussed.

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खडा नहीं हुआ)

हरियाणा लोकसेवा आयोग के कार्यकरण पर प्रतिवेदन वार्शिक।

Home Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I bet to move-

That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 which was laid on the Table of the House on the 15th May, 1975 be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission from 1st April, 1973 to 31st March, 1974 which was laid on the Table of the House on the 15th May, 1975 be discussed.

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खडा नहीं हुआ)

Mr. Speaker: The House stands adjourned Sine die,

10.00 बजे

(तब सभा अनिि चत काल के लिए *स्थगित हुई।)